

राजपत्र हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 30 जुलाई, 1994/ 8 श्रावण, 1916

िनाबन प्रदेश गरकार

PERSONNEL DEPARTMENT (Secretariat Administration Services-1)

ORDER

Shimla-2, the 19th July, 1994

No. Per. (SA-11) B (4)-30/89.—Whereas, Shri Salim Mohammed, Clerk in Himachal Pradesh Secretariat was charge-sheeted under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification. Control and Appeal) Rules, 1965 vide this Department memo, of even number, dated 4th August, 1990 on the following charges:—

Article of charge-I.—that Shri Salim Mohammed has contracted second marriage without obtaining prior permission of the Government.

** Article of charge-11.—that he has contracted second marriage without prior permiss on of the Government whereas a Government servant is prohibited from doing so under Rule 21 of CCS (Conduct) Rules, 1964 and for which he has rendered himself liable to disciplinary action under Rule 14 of CCS(CC&A) Rules, 1965.

2004-य नपन / 94-30-7-94---1,209.

(2141)

1, 89911.1

- 2. Whereas, the Director. Departmental Enquiries was appointed as the Enquiry Officer under Rule 14 (2) of the CCS(CC&A) Rules, 1965 in this case vide this Department office order of even number, dated 4th December, 1990.
- 3. And whereas, the Enquiry Officer has submitted the enquiry report vide letter No. Per(Vig)F-3 (SAS)-184/90, dated 1-5-1992, containing the following findings:—

The Charge No. I, against Shri Salim Mohammed. Clerk of Himachal Pradesh Secretariat is fully substantiated and proved beyond any shadow of doubt; the article of Charge No. II against the charged official Shri Salim Mohammed is fully established and proved beyond any shadow of doubt.

- 4. And whereas, the charged official, Shri Salim Mohammed, Clerk has been given an opportunity to profer representation against the said inquiry report delivered to him vide memo, of even number dated 18th May, 1994 through the Deputy Commissioner, District Bilaspur; and he received it on 2nd June, 1994; he was required to submit his representation within 15 days from the date of its receipt; but till 22nd June, 1994, he has not submitted any representation against the said enquiry report.
- 5. On a carefuly consideration of the enquiry report, undersigned is of the opinion that charges levelled against the delinquent official regarding contracting second marriage without obtaining prior permission of the Government are proved beyond any shadow of doubt and as such his conduct is violative of Rule 21 of CCS(Conduct) Rules, 1964; and therefore, he is liable for punishment under Rule 14 of the CCS(CC&A) Rules, 1965.
- 6. Now, therefore, the undersigned, in exercise of the powers vested in him vide Rule-15(4) of the CCS(CC&A) Rules, 1965, hereby awards the penalty of removal from Government service with immediate effect.

Sd/-

Chief Secretary.

नामान्य प्रशासन विभाग

अविस चना

शिनला-2, 19 जुलाई 1994

संख्या जी 0 ए 0 डी 0 - सी 0 (जी 0 आई) (6) S/91. — -इस विनाग की समसंख्यह अधिसूच्या दितां र 22 जून, 1994 में कन संख्या 3 में ग्रांकित ''श्री सुगील वनारपा" के स्थान पर ''श्री सुगील वरों में पूर्व पढ़ा जाये।

म्रा**देशा**नुसार,

आर0 के0 आनन्द, मध्यमचिषा

धम एवं रोजगार विभाग

ग्रधिस्चना

शिमला-2, 6 जुलाई, 1994

संख्या 4-13/83-श्रम-II.—राज्य सरकार ने, हिमाचल प्रदेश राज्य में होटल/रेश्तरां में नियोजन को नतम मजरूरी श्रीधनियम, 1948 की अनुसूची के भाग-1 में जोड़ने की श्रपने श्राह्मय की हूचना हित्बद क्तियों द्वारा आक्षेप/सुझाय दाखिल करने के लिए राजग्रत में तारीख 16-10-93 को प्रकाणित तमसंस्वक धिसूचना तारीख 16-9-93 द्वारा दी ।;

- और तथाकथित अधिसूचना में नियत अविध के दौरान कोई आक्षेत्र/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।
- 3. ग्रतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी म्रधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "हिमाचल प्रदेश में होटलों/रेस्तरां में नियोजन" की न्यूनतम तदूरी ग्रधिनियम, 1948 की श्रनुसूची के भाग-1 के श्रधीन एक नियोजन के रूप में जोड़ते हैं।

जादेश द्वारा,

एस० एस० सिङ्क्, जित्सायुक्त एवं समिन ।

Authoritative English text of this Government notification No. 4-13/83-Shram-II, duted 6-7-1994 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th July, 1994

- No. 4-13/83-Shram-II.—Whereas the State Government gave notice of its intention add the employment in Hotels/Restaurants in the State of Himachal Pradesh to part-I f schedule to the Minimum Wages Act, 1948 for filing objections/suggestions by the per-ons interested vide notification of even number dated 16-9-93 published in Raipatra ated 16-10-93;
- 2. And whereas no objections/suggestions have been received within the period stiputed in the said notification.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 of the Minimum ages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to add e Employment in Hotels/Restaurants in Himachal Pradesh as one of the employments ader Part I to the schedule of the Minimum Wages Act, 1948.

By order,

S. S. SIDHU,

स्वारूथ एवं परिवार वहवाण विभाग

यधिषु बना

शिमना-2, 7 जुलाई, 1994

संख्या एय 0 एक 0 उच्चयू 0-की 0 (ए) 2-4/88-पार्ट-! -- द्विमाधल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की मधियूनना संख्या स्व 0-व (म) 3-1/80-11, तारीख 28-10-89 के अधिकमण में तथा जन्य और मृत्यु रिक्ट्रिकरण
प्रिषिनियम्, 1960 की धारा 4 की उन धारा (2) द्वारा प्रदेश जिल्लायों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश,
निदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार अल्याण के उप निदेश (गागिक रिजिस्ट्रिकरण) को मृत्य रिजिस्ट्रार के
प्रवोक्षण और निदेश के संधीत, उच मृत्य रिजिस्ट्रार के हुए में, ऐन इन्हों का निवंहन करने के लिए नियुका तरने हैं जिनका अनुमालन करने के लिए उक्का अधिनियम के प्रयोग अन्हों समय-समेन पर मुख्य रिजिस्ट्रार,
दिमाचन प्रदेश द्वारा प्राधिकन किया जन्य।

ग्रादेण द्वारा.

जेश पीत नेगी, प्रायुक्त एवं सचिन।

[Authoritative English text of this department notification No. HFW-B(A)2-4/88-Part-I dated 7-7-94 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimba-2, the 7th July, 1994

No. HFW-B(A)2-4/88-Part-I—In supersession of this department notification No. HFW-B(A)3-1/80-Part-II dated 28-10-36 and in exercise of powers conferred by section 4(2) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (Act No. 18 of 1969), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to appoint the Deputy Director (Civil Registration), Directorate of Health Services, Himachal Pradesh, as Deputy Registrar, Births and Deaths Himachal Pradesh, for discharging such functions, under the superintendence and direction of the Chief Registrar, as may be authorised by the Chief Registrar Himachal Pradesh, to perform under the Act ibid from time to time.

By order.

J. P. NEGI, Commissioner-cun-Secretary.

यामीण विधास एवं पंचायती सुध विभाग

छश्चिसूचना

शिगल्या-2, 14 ज्लाई, 1994

मंद्र्या पी 0सी 0 एवं 0-एवं 9ए 0 (3) -5/34 ्राइय विभाग की समसंख्यात अधिस्वता, दिर्ताण 16-6-1994 के अस्तर्गत जिला पिर्कीय, विरास खण्ड पद्धार की आत सभा "गैना भारटी" की नाम एवं मुख्यवास को वदनकर "डिल्क्षण" रखने हेतु गांव सभा के समस्त सदस्य से आपत्तियों एवं मुसाब आपत्तियों पिए गए थे ;

2

 $\overline{2149}$

र्यार क्योंकि उक्त अिस्चिना के आरी होने के दिनांक में 15 दिनों की सनिध के शितर इस सम्बन्ध में विभाग में कोई भी साथक्रि एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुई है।

मतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शिवानों के श्रधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज म्रिधितयम, 1994 की धारा 3(2) (ग) (घ) के अनार्गत प्राप्त है, जिला विरमौर, विकास खण्ड पच्छाद की ग्राम मभा "नैना धारटी" का नाम बदल कर ग्राम सभा "डिल्यन" रखने एवं ग्राम सभा के सुक्ष्यास की "डिल्यन" निर्याखित करने के सहर्ष मादेण प्रदान करते हैं।

यादेश द्वारा,

ं हर ताक्षरित/-शतिरिक्त मुख्य सचिव ।

नगर एवं प्राय योजना विभाग

चश<u>्चिय</u>ूचना

शिमला-2, 8 जून/14 जुलाई, 1994

संख्या टी 0 सी 0पी 0-एफ (6)-13/94 —िहमा चल प्रदेश नगर एवं ग्राय योजना प्रधिति ता, 1977 की धारा _ 13 के ग्रधीन ग्रधिसूचना संख्याः पी 0 बी 0 डब्ल्यू 0 (बी 0 एण्ड ग्रार0) (बी) 26-33/86 दिनां 0 30-7-86 द्वार् इतहीजी योजना क्षेत्र का गठन कर दिया गया है;

भीर उन्त योजना क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग नक्षों भो तूर्वीका प्रश्लितियम की धारा 15 के अधीन प्रशाशित नहीं किया गया है ;

श्रीर हिमाचल प्रदेश क राज्यवाल का समाधान हो गया है कि पूर्वीक्त योजना क्षेत्र में उपयोग की गई भूगि में परिवर्तन करने श्रीर उसमें किसी भवन के निर्माण करने से गतह या किसी भूमि या गिट्टी को क्षति पहुंचने की पम्भावना है या यह मिट्टी के पिरिस्थण, भूमि के खिपकों की रोज्यान या कटाव से संरक्षण के लिए हानिकार के हु श्रीर उक्त श्रीविनयम के उपवन्धों के श्रनुसार उक्त क्षेत्र की योज ।। वनाना श्रीर उसका विकास करना कठिन हो गा। है।

श्रतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना श्रीधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (1) ढारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ारते हुए डलहीजी योजना थेते के विद्यान भूमि उपयोगको इस श्रीधमूचना के जारो होते की नारीख से तीन वर्ष की श्रवधि के लिए बन्द करने हैं।

यादेश द्वारा,

पी 0 एय-0 नेगी, वित्तापुक्त एवं पन्तिव । [Authorised English text of this Department notification No. T. C. P.-F.(6)-13-94 dated 8-6-94 as required under article 348(3) of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th June, 1994

No. T.C.P.-F (6)-13/94.—Whereas Dalhousie Planning Area has been constituted under section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, vide notification No. PBW(B and R) (B) 26-33/86 dated 30-7-1986;

And whereas existing landuse map of the said planning area as not yet been published under section 15 of the Act ibid.

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that in the aforesaid Planning Area, the change of landuse or any building operation therein is likely to cause injurious disturbance of the surface or any land or soil, or is deterimental to preservation of the soil, prevention of land slips or protection against erosion and is likely to make it difficult to plan and develop the said area in accordance with the provisions of the aforesaid Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to freeze the existing landuse of Dalhousie Planning Area from the date of the issue of this notification for a period of 3 years.

By order,

P. S. NEGI, Financial Commissioner-cum-Secretary.